

# HRA an USIUN The Gazette of India

# असाधारगा EXTRAORDINARY

भाग II—सण्ड 3—उप-सण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 337] No. 337] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 1981/आवाद 29, 1903 NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 1981/ASADHA 29, 1903

इस भाग में भिन्म पूछ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रक्का जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compliation

# उदयोग मंत्रालय

(अवियोगिक विकास विभाग)

### आबेश

नर्षे दिल्ली, 20 ज्लाई, 1981

का. आ. 575 (अ).—भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (अौद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. 375 (अ), तारील 22 जुलाई, 1975 द्वारा (जिसमे इसके परनात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स ग्यूकोनेट लि., कलकत्सा नामक औद्योगिक उपक्रम के प्रबंध को उक्त आदेश में निर्विष्ट ध्यक्तिय के निकाय ई 21 जुलाई, 1977 तक जिसमें यह तारील भी सम्मिलित है, दो वर्ष की अविध के लिए ग्रहण कर लिया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का. आ. 405 (अ), तारील 20 जून, 1977 द्यारा उक्त आदेश को 21 ज्लाई, 1979 तक की, जिसमें यह तारील भी सम्मिलित है, दो वर्ष की और अविध के लिए बढ़ा दिया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 408 (अ), तारीख 16 ज्लाई, 1979 व्यारा उक्त आदेश की कालाविध 21 जुलाई, 1980 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अविध के लिए बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के बादेश सं. का. आ. 556 (अ), तारीस 21 जुलाई, 1980 द्वारा उक्त आदेश की कालाविध 21 जुलाई, 1981 तक, जिसमों यह तारीस भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अविध के लिए बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समी-चीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त व्यक्तियों के निकाय हारा 21 जूलाई, 1982 तक की, जिसमें यह तारील भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि तक जारी रक्षा जाना चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उब्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती हैं कि उक्त आदेश 21 ज्लाई, 1982 तक जिसमें यह तारीब भी सिमालित है, एक वर्ष की और अविधि तक प्रभावी रहेगा ।

[फा. सं. 6 (3)/79-सी. यू. एस.] चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त समिध

### MINISTRY OF INDUSTRY

## (Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 20th July, 1981

S.O. 575(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 375(E) dated the 22nd July, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Gluconate Limited, Calcutta, had been taken over by the body of persons referred to in the said Order for a period of two years up to and inclusive of the 21st July, 1977;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 405(E) dated the 20th June, 1977, the duration of the said Order was extended for a further period of two years up to and inclusive of the 21st July, 1979;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Deve-

lopment) No. S.O. 406(E), dated the 16th July, 1979, the duration of the said Order was extended for a further period of one year up to and inclusive of the 21st July 1980;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 556(E), dated the 21st July, 1980, the duration of the said Order was extended for a further period of one year up to and inclusive of the 21st July, 1981;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said body of persons should continue for a further period of one year up to and inclusive of the 21st July, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year up to and inclusive of the 21st July, 1982.

[F. No. 6(3)/79-CUS] C. K. MODI, Jt. Secy.